



शैल खबर

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाइन साप्ताहिक

निष्पक्ष
एवं
निर्भाविक
साप्ताहिक
समाचार



www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 42 अंक - 44 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 06 - 13 नवम्बर 2017 मूल्य पांच रुपए

कुछ क्षेत्रों में वीरभद्र का विद्रोहियों की पीठ थपथपाना और कुछ में शान्ता का सक्रिय न रहना त्रिशंकु के स्पष्ट संकेत

शिमला/शैल। मतदान के बाद सामने आये आंकड़ों के अनुसार 37,21,665 मतदाताओं ने इन चुनावों में वोट डाले हैं। इनमें भी महिला मतदाताओं की संख्या 19,10,535 और पुरुषों की संख्या 18,11,126 रही है। इसमें पुरुषों का प्रतिशत 71.55 और महिलाओं का 77.76 रहा है। 6% महिलाओं का आंकड़ा अधिक रहा है। विधानसभा क्षेत्रों की गणना में 39 क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अधिक रही है। इसी के साथ यह भी गैरतलब है कि सिरमौर, सोलन, शिमला, कुल्लु, लाहौल स्पिति और किन्नौर के एक भी विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक नहीं रही है। जबकि कागंड़ा, ऊना, हमीरपुर के हर क्षेत्र में महिलाओं की संख्या अधिक रही है। मण्डी में भी दस में से आठ हल्कों में महिलाओं की संख्या अधिक रही है। इन आंकड़ों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव परिणाम महिलाओं से ही प्रभावित रहेगे। लेकिन यह दिलचस्प रहा है कि आधे हिमाचल में महिलायें पुरुषों से अधिक तो आधे में कम रही हैं।

इससे यह सवाल उठना स्वभाविक है कि महिलाओं के मतदान में इस तरह का आचरण क्यों रहा है। बल्कि इस आंकड़े से यह भी उभरता है कि पूरे प्रदेश में महिलाओं का आंकड़ा 6% अधिक रहा है पुरुषों से। इससे यह भी लगता है कि आधे हिमाचल में चुनाव परिणाम महिलाओं के अधिक आने से तो आधे में कम आने से प्रभावित होंगे। इस परिदृश्य में यह समझना आवश्यक हो जाता है कि महिलाओं पर किन चीजों का चुनाव के संदर्भ में प्रभाव रहा होगा। इसमें सबसे पहले मंहगाई की गिनती आती है क्योंकि अभी थोड़े से ही अन्तराल में रसोई गैस सिलेण्डर की कीमत में 80 रुपये की बढ़ौतरी देखने को मिली है और इस पर सबसे अधिक चिन्ता महिलाओं ने व्यक्त की है। यदि बढ़ती कीमतों

के प्रति महिलाओं में आक्रोश रहा होगा तो इसका नुकसान भाजपा को होगा क्योंकि इसके लिये राज्य सरकार की बजाये केन्द्र सरकार ज्यादा जिम्मेदार है। लेकिन इसी के साथ जब कोटखाई का गुड़िया प्रकरण सामने आया तब प्रदेश में महिला सुरक्षा एक बड़े मुद्दे के रूप में उभर कर सामने आया। शिमला में हर रोज गुड़िया को न्याय मांगने वालों के धरने - प्रदर्शन देखने को मिले हैं। लेकिन जब यह प्रकरण सीबीआई को सौंप दिया गया और सीबीआई भी इसमें कुछ ठोस नहीं कर पायी तब गुड़िया आन्दोलन की आंच भी धूमी पड़ती चली गयी। चुनाव आने तक यह मुद्दा तो बड़ा मुद्दा बनकर नहीं रह पाया हालांकि भाजपा ने इसे अपने अभियान का एक अंग अन्त तक बनाये रखा। लेकिन मतदान में पूरे शिमला, सोलन, सिरमौर में महिलाओं की भागीदारी का कम रहना एक अलग ही स्थिति खड़ी कर देता है। इसी के साथ सिरमौर, सोलन, शिमला, कुल्लु के 18 विधानसभा क्षेत्रों में पुरुष मतदाताओं की संख्या महिलाओं के अनुपात में इतनी अधिक है कि वहां पर निश्चित रूप से पुरुष ही चुनाव परिणाम को प्रभावित करेंगे। प्रदेश के 52 चुनाव क्षेत्र इन आंकड़ों के अनुसार ऐसे हैं जहां हार - जीत का फैसला यह महिला और पुरुषों का अन्तर तय करेगा। चुनावी मुद्दों के नाम पर भाजपा ने भ्रष्टाचार को जिम्मेदारी से केन्द्रित करने का प्रयास किया वह अन्त तक आते - आते उसी पर भारी पड़ गया। क्योंकि इस भ्रष्टाचार पर प्रचार के अनुरूप केन्द्रीय जांच ऐजेन्सीयां कारबाई नहीं कर पायी हैं। फिर भ्रष्टाचार के जिस तरह के आरोप कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ रहे हैं ठीक वैसे ही आरोप भाजपा नेतृत्व के खिलाफ भी रहे हैं। वीरभद्र सिंह ने चुनाव के अन्तिम चरण में भाजपा पर पलटवार करते हुए यह जवाब दिया कि भाजपा नेता प्रेम कुमार धूमल,

और माकपा के जीतने की संभावना है और सरकार बनाने में इन्हीं की भूमिका अहम रहेगी। क्योंकि कुछ स्थानों पर वीरभद्र ने खुलकर अपने विरोधियों को आशीर्वाद दिया है वे विशंकु के वहीं पर कुछ क्षेत्रों में शान्ता कुमार

का सक्रिय न रहना त्रिशंकु के स्पष्ट संकेत माने जा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में वीरभद्र का विद्रोहियों की पीठ थपथपाना और कुछ में शान्ता का सक्रिय न रहना त्रिशंकु के स्पष्ट संकेत माने जा रहे हैं।

महिला मतदान के महत्वपूर्ण आंकड़े

कई चुनाव क्षेत्रों में पुरुष और महिला मतदाताओं में इतना अन्तर है कि उसके आंकलन का सारा गणित अपने में ही कई सवाल खड़े कर देता है। महत्वपूर्ण अन्तर वाले क्षेत्र यह हैं: इनमें वोट डालने वाले पुरुषों और महिलाओं की संख्या इस प्रकार है:-

चुनाव क्षेत्र	पुरुष मतदाता	महिला मतदाता
1. भटियात	24739	27152
2. नूरपुर	30757	32514
3. फतेहपुर	26420	31104
4. ज्वाली	29892	35783
5. देहरा	24125	29280
6. जसवां परागपुर	23212	27794
7. ज्वालामुखी	23451	29379
8. जयसिंहपुर	20986	27930
9. सुलह	30235	37873
10. नगरोटा	29433	33873
11. कांगड़ा	26931	30732
12. शाहपुर	27863	31548
13. धर्मशाला	26923	28588
14. पालमपुर	23213	26440
15. बैजनाथ	23319	28572
16. जोगिन्द्रनगर	27893	36907
17. धर्मपुर	20842	26109
18. मण्डी	24525	27643
19. बल्ह	26774	29718
20. सरकाघाट	24679	30945
21. भेरंज	21350	27875
22. सुजारनपुर	21728	27946
23. हमीरपुर	21458	26029
24. बड़सर	24091	31537
25. नादौन	27167	34325
26. चिन्तपुरनी	27170	29393
27. गगरेट	28119	30733
28. हरोली	30045	33493
29. ऊना में	29635	32086
30. कुटलैहड़	27255	31230
31. झाण्डूता	24758	27924
32. घुमारवीं	26587	32257
33. बिलासपुर	27367	29934

राज्यपाल ने किया अन्तर्राष्ट्रीय लवी मेले का उद्घाटन मानव कल्याण समिति अर्का का युवाओं को नशे से मुक्त करने पर जोर

शिमला / शैल। राज्यपाल आचार्य देवब्रत ने शिमला जिले के रामपुर बृशौहर में चार दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय लवी मेले का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति, रीति-रिवाजों और परम्पराओं के लिए प्रसिद्ध है जिसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि राज्य के लोग मेलों व उत्सवों



को बहुत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि मेले और उत्सव की राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और यह जरूरी है कि पुरातन वैभव को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किये जाएं। उन्होंने कहा कि आज लड़कियां ही क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहीं हैं, जिन्हें और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं को अपनी ऊर्जा सामाजिक कार्यालय और ज्ञानवर्द्धन में लगानी चाहिए ताकि वे समाज की भलाई में अपना योगदान दे सकें।

उन्होंने कहा कि यह मेला

आचार्य देवब्रत ने लोगों का आयोजन किया कि भूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए सभी मिलकर आगे आएं। उन्होंने कहा कि आज लड़कियां ही क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहीं हैं, जिन्हें और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं को अपनी ऊर्जा सामाजिक कार्यालय और ज्ञानवर्द्धन में लगानी चाहिए ताकि वे समाज की भलाई में अपना योगदान दे सकें।

नागालैंड के किसानों ने सीखी नौणी विवि में पहाड़ी खेती की बारी किया

असम राइफल्स द्वारा प्रायोजित था 22 किसानों का प्रतिनिधिमंडल

इस हिमाचल दौरा को रखाना किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भेजर गुलशन कुमार कर रहे हैं। उनके साथ असम राइफल्स के प्रशासनिक कर्मचारी भी हैं।

भेजर गुलशन ने बताया कि दौरे

भारत और तिब्बत के मध्य सदियों से प्रचलित एक महत्वपूर्ण व्यापार मेला है और अपनी तरह का एक गौरवशाली, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक इतिहास और हिमाचल प्रदेश की विरासत का एक अनूठा उदाहरण है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विभिन्न जिलों के लोक कलाकार लवी मेले की सांस्कृतिक संध्याओं में अपने प्रदर्शन से सभी का मनोरंजन करेंगे।

राज्यपाल ने 'किन्नौरी मार्किट' का भी शुभारम्भ किया और इस अवसर पर विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य संगठनों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में गहरी रुचि दिखाई।

इससे पूर्व उन्होंने रामपुर बाजार का दौरा किया और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की। बाजार में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के लिए उन्होंने नगर परिषद् व व्यापार मंडल को बधाई दी।

उपायुक्त एवं लवी मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष रोहन चंद ठाकुर ने राज्यपाल का स्वागत तथा मेले की गतिविधियों वारे विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने राज्यपाल को किन्नौरी टोपी, शॉल तथा स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया।

एसडीएम नियुण जिंदल ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये गये।

राज्यपाल के सलाहकार शशिकान्त शर्मा, नगर परिषद् के सदस्यगण, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

उन्होंने लवी मेले की समृद्ध परम्पराओं को संजोए रखने के लिए आयोजन समिति की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हीं कपड़े, सूखे मेवे और अन्य पारम्परिक शिल्प और मेले में प्रदर्शित उत्पाद अपने आप में अनूठे हैं। यह मेला पारम्परिक शिल्पकारों और किसानों के हित के साथ - साथ इन उत्पादों के प्रचार - प्रसार व विक्रय के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है।

राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने लवी मेले की समृद्ध परम्पराओं को संजोए रखने के लिए आयोजन समिति की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हीं कपड़े, सूखे मेवे और अन्य पारम्परिक शिल्प और मेले में प्रदर्शित उत्पाद अपने आप में अनूठे हैं। यह मेला पारम्परिक शिल्पकारों और किसानों के हित के साथ - साथ इन उत्पादों के प्रचार - प्रसार व विक्रय के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने लवी मेले की समृद्ध परम्पराओं को संजोए रखने के लिए आयोजन समिति की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हीं कपड़े, सूखे मेवे और अन्य पारम्परिक शिल्प और मेले में प्रदर्शित उत्पाद अपने आप में अनूठे हैं। यह मेला पारम्परिक शिल्पकारों और किसानों के हित के साथ - साथ इन उत्पादों के प्रचार - प्रसार व विक्रय के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने लवी मेले की समृद्ध परम्पराओं को संजोए रखने के लिए आयोजन समिति की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हीं कपड़े, सूखे मेवे और अन्य पारम्परिक शिल्प और मेले में प्रदर्शित उत्पाद अपने आप में अनूठे हैं। यह मेला पारम्परिक शिल्पकारों और किसानों के हित के साथ - साथ इन उत्पादों के प्रचार - प्रसार व विक्रय के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने लवी मेले की समृद्ध परम्पराओं को संजोए रखने के लिए आयोजन समिति की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हीं कपड़े, सूखे मेवे और अन्य पारम्परिक शिल्प और मेले में प्रदर्शित उत्पाद अपने आप में अनूठे हैं। यह मेला पारम्परिक शिल्पकारों और किसानों के हित के साथ - साथ इन उत्पादों के प्रचार - प्रसार व विक्रय के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने लवी मेले की समृद्ध परम्पराओं को संजोए रखने के लिए आयोजन समिति की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हीं कपड़े, सूखे मेवे और अन्य पारम्परिक शिल्प और मेले में प्रदर्शित उत्पाद अपने आप में अनूठे हैं। यह मेला पारम्परिक शिल्पकारों और किसानों के हित के साथ - साथ इन उत्पादों के प्रचार - प्रसार व विक्रय के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने लवी मेले की समृद्ध परम्पराओं को संजोए रखने के लिए आयोजन समिति की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हीं कपड़े, सूखे मेवे और अन्य पारम्परिक शिल्प और मेले में प्रदर्शित उत्पाद अपने आप में अनूठे हैं। यह मेला पारम्परिक शिल्पकारों और किसानों के हित के साथ - साथ इन उत्पादों के प्रचार - प्रसार व विक्रय के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने लवी मेले की समृद्ध परम्पराओं को संजोए रखने के लिए आयोजन समिति की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हीं कपड़े, सूखे मेवे और अन्य पारम्परिक शिल्प और मेले में प्रदर्शित उत्पाद अपने आप में अनूठे हैं। यह मेला पारम्परिक शिल्पकारों और किसानों के हित के साथ - साथ इन उत्पादों के प्रचार - प्रसार व विक्रय के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने लवी मेले की समृद्ध परम्पराओं को संजोए रखने के लिए आयोजन समिति की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हीं कपड़े, सूखे मेवे और अन्य पारम्परिक शिल्प और मेले में प्रदर्शित उत्पाद अपने आप में अनूठे हैं। यह मेला पारम्परिक शिल्पकारों और किसानों के हित के साथ - साथ इन उत्पादों के प्रचार - प्रसार व विक्रय के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने लवी मेले की समृद्ध परम्पराओं को संजोए रखने के लिए आयोजन समिति की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हीं कपड़े, सूखे मेवे और अन्य पारम्परिक शिल्प और मेले में प्रदर्शित उत्पाद अपने आप में अनूठे हैं। यह मेला पारम्परिक शिल्पकारों और किसानों के हित के साथ - साथ इन उत्पादों के प्रचार - प्रसार व विक्रय के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने लवी मेले की समृद्ध परम्पराओं को संजोए रखने के लिए आयोजन समिति की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हीं कपड़े, सूखे मेवे और अन्य पारम्परिक शिल्प और मेले में प्रदर्शित उत्पाद अपने आप में अनूठे हैं। यह मेला पारम्परिक शिल्पकारों और किसानों के हित के साथ - साथ इन उत्पादों के प्रचार - प्रसार व विक्रय के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने लवी मेले की समृद्ध परम्पराओं को संजोए रखने के लिए आयोजन समिति की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हीं कपड़े, सूखे मेवे और अन्य पारम्परिक शिल्प और मेले में प्रदर्शित उत्पाद अपने आप में अनूठे हैं। यह मेला पारम्परिक शिल्पकारों और किसानों के हित के साथ - साथ इन उत्पादों के प्रचार - प्रसार व विक्रय के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने लवी मेले की समृद्ध परम्पराओं को संजोए रखने के लिए आयोजन समिति की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हीं कपड़े, सूखे मेवे और अन्य पारम्परिक शिल्प और मेले में प्रदर्शित उत्पाद अपने आप में अनूठे हैं। यह मेला पारम्परिक शिल्पकारों और किसानों के हित के साथ - साथ इन उत्पादों के प्रचार - प्रसार व विक्रय के लिए उपयुक्त अवसर प्र

प्रदेश में शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ मतदान

शिमला / शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुष्टेन्द्र राजपूत ने बताया कि प्रदेश की सभी 68 विधानसभा



क्षेत्रों में मतदात शांतिपूर्वक सम्पन्न

हुआ और प्रदेश के किसी भी भी भाग से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।

उन्होंने कहा कि राज्य मुख्यालय में प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में लगभग 74 प्रतिशत रिकार्ड मतदान दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि चम्बा जिला में लगभग 74 प्रतिशत, हमीरपुर में 69.50 प्रतिशत, शिमला 72.5 प्रतिशत, सोलन 77.44 प्रतिशत, मण्डी 75 प्रतिशत, कांगड़ा 72, कुल्लू 77.9, सिरमौर 82 प्रतिशत, लाहौल-स्पीति 73.4 प्रतिशत, बिलासपुर 75 तथा किन्नौर जिला में 75 प्रतिशत दर्ज किया

किया गया।

उन्होंने कहा कि राज्य मुख्यालय के प्रति खासा उत्साह देखा गया। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक मत प्रतिशत ता सिरमौर जिला में लगभग 82 प्रतिशत दर्ज की गई जबकि सबसे कम मतदान हमीरपुर जिला में लगभग 69.5 प्रतिशत रहा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के लोगों का राज्य में शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव सम्पन्न होने तथा चुनाव प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित बनाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

ईवीएम व वीवीपैट मशीनों कड़े सुरक्षा पहरे में केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों की 23 कम्पनियां तैनात

शिमला / शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुष्टेन्द्र राजपूत

बलों की 23 कम्पनियां इन मशीनों की सुरक्षा व निगरानी के लिए



ने कहा कि प्रदेश भर में ईवीएम तथा वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबन्ध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन मशीनों की सुरक्षा के लिए त्रि-स्तरीय सुरक्षा प्रणाली लागू की गई है। केन्द्रीय अर्द्ध-सैन्य

तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 48 स्थानों पर ईवीएम तथा वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा के लिए 100 स्ट्रॉग रूम स्थापित किए गए हैं जो 24 घण्टे सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे।

आदर्श चुनाव आवार संहिता लागू होने के बाद 288 शिकायतें प्राप्त, 278 का निपटारा

शिमला / शैल। निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरान्त आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की कुल 288 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 278 का निपटारा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग को मतदान के दिन तीन शिकायतें प्राप्त हुई जो सभी चम्बा जिला से सम्बन्धित थीं जिनका निपटारा कर लिया गया है।

उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में स्थापित शिकायत कक्ष में अन्य प्रकार की दो शिकायतें प्राप्त हुई जो आम लोगों द्वारा भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि विभाग के पास प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया आरम्भ होने के उपरान्त इस प्रकार की कुल 205 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 90 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है।

District	Name of Constituency	Votes Cast	% age
Chamba	1-Churah (SC)	52094	76.13
	2-Bharmour (ST)	51452	72.23
	3-Chamba	53600	71.35
	4-Dalhousie	48638	73.21
	5-Bhatiyat	51891	73.35
Total poll % age in District Chamba		257675	73.21
Kangra	6-Nurpur	63271	76.92
	7-Indora (SC)	59139	72.23
	8-Fatehpur	57524	72.03
	9-Jwali	65675	73.61
	10-Dehra	53405	70.74
	11-Jaswan Pragpur	51006	70.30
	12-Jwalamukhi	52830	73.92
	13-Jaisinghpur (SC)	48916	63.91
	14-Sulah	68108	71.64
	15-Nagrota	63303	77.98
	16-Kangra	57663	76.38
	17-Shahpur	59411	74.80
	18-Dharmshala	55511	74.55
	19-Palampur	49653	71.92
	20-Baijnath (SC)	52071	65.64
Total poll % age in District Kangra		857486	72.47
Lahaul & Spiti	21-Lahaul & Spiti (ST)	16879	73.40
	Total poll % age in District Lahaul & Spiti	16879	73.40
Kullu	22-Manali	52674	79.40
	23-Kullu	61739	75.79
	24-Banjar	53060	80.37
	25-Anni (SC)	59482	76.63
Total poll % age in District Kullu		226955	77.87
Mandi	26-Karsog (SC)	50711	75.48
	27-Sundernagar	56409	76.29
	28-Nachan (SC)	60478	78.37
	29-Seraj	62091	83.20
	30-Drang	62599	78.75
	31-Jogindernagar	64800	72.40
	32-Dharmpur	46951	64.22
	33-Mandi	52468	76.37
	34-Balh (SC)	56492	80.13
	35-Sarkaghat	55624	67.99
Total poll % age in District Mandi		568623	75.21
Hamirpur	36-Bhoranj (SC)	49225	65.84
	37-Sujanpur	49674	74.07
	38-Hamirpur	47487	69.11
	39-Barsar	55628	70.01
	40-Nadaun	61492	71.98
	Total poll % age in District Hamirpur	263506	70.19
Una	41-Chintpurni (SC)	56563	73.15
	42-Gagret	58852	77.77
	43-Haroli	63538	78.96
	44-Una	61721	78.06
	45-Kutlehar	58485	74.21
	Total poll % age in District Una	299159	76.45

District	Name of Constituency	Votes Cast	% age
Bilaspur	46-Jhandutta (SC)	52682	73.54
	47-Ghumarwin	58845	72.86
	48-Bilaspur	57301	74.67
	49-Sri Nainadevi ji	55296	82.04
	Total poll % age in District Bilaspur	224124	75.58
Solan	50-Arki	63107	74.63
	51-Nalagarh	69153	84.27
	52-Doon	55464	88.95
	53-Solan (SC)	53999	66.65
	54-Kasauli (SC)	47882	74.86
Total poll % age in District Solan		289605	77.44
Sirmour	55-Pachhad (SC)	54863	79.84
	56-Nahan	61468	82.48
	57-SriRenuka ji (SC)	51167	78.29
	58-Paonta Sahib	60271	80.43
	59-Shillai	55143	84.18
Total poll % age in District Sirmour		282912	81.05
Shimla	60-Chopal	54789	75.20
	61-Theog	57153	73.02
	62-Kasumpti	40909	66.97
	63-Shimla (Urban)	32137	63.76
	64-Shimla (Rural)	52319	73.05
Total poll % age in District Shimla		393428	72.68
Kinnaur	65-Jubbal-Kothkhai	53918	80.24
	66-Rampur (SC)	52643	74.25
Total poll % age in District Kinnaur		3721665	75.09
Male	Female	Third Gender	Total % age
Registered Voters	2531321	2457032	14 4988367
Votes Cast	1811126	1910535	4 3721665 74.61

योग्य सहायकों के बिना निर्णय करना
बड़ा कठिन होता है।चाणक्य

टेक्स्ट सम्पादकीय

जीएसटी रक्त के बद...

जीएसटी परिषद् ने 177 वस्तुओं को 28% के दायरे से बाहर करके 18% के दायरे में ला दिया है। यह फैसला अभी 15 नवम्बर से ही लागू हो जायेगा और इससे इन वस्तुओं की कीमतें में कमी आयेगी यह माना जा रहा है। जीएसटी जब से लागू हुआ था तभी से व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग इसका विरोध कर रहा था। व्यापारी इस कारण विरोध कर रहे थे कि इससे कर अदा करने में प्रक्रिया संबंधी सरलता के जो दावे किये जा रहे थे वह वास्तव में सही नहीं उत्तरे। लेकिन व्यापारी के साथ ही आम आदमी भी उपभोक्ता के रूप में इससे परेशान हो उठा क्योंकि खरीददारी के बाद कुल बिल पर जब जीएसटी के नाम पर कर वसूला जाने लगा तो उसे इस जीएसटी के कारण मंहगाई होने का अहसास हुआ। इससे पहले भी वह यही खरीददारी करता था परन्तु उस समय उसे जीएसटी के नाम से अलग अदायगी नहीं करनी पड़ती थी आज जब जीएसटी अलग से बिल में जुड़ता है तब वह इसका विरोध नहीं कर पाता है। जीएसटी को लेकर जब लोगों में नाराज़गी उभरी तब इस पर भाजपा के ही पूर्व वित्त मन्त्री रहे यशवंत सिन्हा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, पूर्व मन्त्री अरुणी शौरी जैसे बड़े नेताओं के विरोधी स्वर भी उभर कर सामने आ गये। राहुल गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स की संज्ञा दे दी। हिमाचल के चुनाव प्रचार अभियान में जब भाजपा के केन्द्रिय नेता प्रदेश में आये और पत्रकारा वार्ताओं के माध्यम से मीडिया से रूबरू हुए तब उन्हें जीएसटी पर भी सवालों का समाना करना पड़ा। जीएसटी पर उठे सवालों के जवाब में भाजपा नेताओं का पहली बार यह स्टैण्ड सामने आया कि इसके लिये मोदी सरकार नहीं बल्कि जीएसटी का ऊसिल जिम्मेदार है। भाजपा नेताओं ने इसके लिये कांग्रेस को भी बराबर का जिम्मेदार कहा और सवाल किया कि इसे वीरभद्र सरकार ने अपने विधानसभा में क्यों पारित किया?

जीएसटी नोटबंदी के बाद दूसरा बड़ा आर्थिक फैसला मोदी सरकार का रहा है। नोटबंदी को लागू हुए पूरा एक वर्ष हो गया है। विपक्ष ने 8 नवम्बर 2016 को काले दिवस के रूप में स्मरण किया है। पूर्व प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को आर्थिक आतंक करार दिया है। नोटबंदी को लेकर मनमोहन सिंह ने जो चिन्ताएं देश के सामने रखी थी वह सब सही साबित हुई है। नोटबंदी के बाद आर्थिक विकास दर में 2% की कमी आयी है इसे रिजर्व बैंक ने भी स्वीकार कर लिया है। भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनावों में पहले ही मोदी को नेता घोषित कर दिया था। लोकसभा का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव से पूर्व स्वामी राम देव और अन्ना आन्दोलनों के माध्यम से देश के भीतर भ्रष्टाचार और कालेधन को लेकर जो तस्वीर सामने रखी गयी थी वह एकदम भयानक और गंभीर थी। देश का आम आदमी उस स्थिति से छुटकारा पाना चाहता था। चुनावों में उसे भरोसा दिलाया गया था कि मोदी की सरकार बनने से अच्छे दिन आयेंगे। इस भरोसे पर विश्वास करके ही जनता ने मोदी के नेतृत्व में भाजपा को प्रचण्ड बहुमत दिलाकर सत्तासीन किया। लेकिन सरकार बनने के आज चौथे साल भी वह अच्छे दिनों का वायदा पूरा नहीं हो पाया है। आम आदमी के लिये अच्छे दिनों का पहला मानक मंहगाई होती है। मंहगाई के मुहाने पर मोदी सरकार बुरी तरह असफल रही है आज आम कहा जा रहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में मंहगाई की स्थिति यह नहीं थी। आज रसोई गैस की कीमत यूपीए शासन के मुकाबले में दोगुनी हो गयी है। पेट्रोल डीजल और सारे खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी वृद्धि आम आदमी के सामने है। बेरोजगारी कम होने की बजाये नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसले से और बढ़ी है।

कालेधन और भ्रष्टाचार के जो आंकड़े 2014 के लोकसभा चुनावों से पूर्व देश के सामने थे वह आज भी वैसे ही रहे हैं। मोदी और उनके सहयोगी जो यह दावा करते आ रहे थे कि उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार का कोई बड़ा काण्ड सामने नहीं आया है। उनका यह दावा आज अमितशाह और अजित डोभल के बेटों पर लगे आरोपों से एकदम बेमानी हो जाता है। जिन बानामा पेपर्ज में नाम आने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ वहां के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पद से भी हटाये जा चुके हैं। वहीं पर भारत सरकार उन पेपर्ज में जिन लोगों के नाम आये हैं उनके खिलाफ कोई मामला तक दर्ज नहीं कर पायी है। अब पैराडाईज़ पेपरज में तो मोदी के मन्त्री और एक राज्य सभा सांसद तक का नाम आ गया है। लेकिन इसपर भी कोई कारवाई नहीं होगी यह माना जा रहा है। क्योंकि जिस लोकपाल के गठन को लेकर अन्ना का इतना बड़ा आन्दोलन यह देश देर चुका है आज मोदी सरकार इतने बड़े बहुमत के बाद भी उस मुद्दे पर पूरी तरह चुप्प बैठी हुई है। इसी से सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ इनमादारी और नीयत का पता चल जाता है। यही कारण है कि कॉमन वैल्य गेम्ज़ और 2 जी जैसे मामलों पर चार वर्षों में कोई एकाईआर तक दर्ज नहीं हो पायी है।

आज जब जीएसटी पर सरकार ने नये सिरे से विचार करके 177 आईटमों को 28% से बाहर करने का फैसला लिया है भले ही यह फैसला गुजरात चुनावों के कारण लिया गया है। फिर भी यह स्वागत योग्य है इसी तर्ज में अब सरकार को चाहिये कि नोटबंदी के बाद कैश लैस और डिजिटल होने के फैसलों को ठण्डे बस्ते में डालकर कॉरपोरेट सैक्टर पर नकेल डालने का प्रयास करें। इस सैक्टर के पास जो कर्ज एनपीए के रूप में फंसा हुआ है उसे वसूलने में गंभीरता दिखाये अन्यथा हालात आने वाले दिनों में सरकार के कन्ट्रोल से बाहर हो जायेगा यह तय है।

क्या विश्व महाविनाश के लिए तैयार है

डॉ नीलम महेंद्रा

अब देखा जाए तो अपने अपने नजरिये से दोनों ही सही हैं।

आज की कड़वी सच्चाई यह है कि विकसित देशों की सुपर पावर बनने की होड़ और उनकी राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं ने वर्तमान परिस्थितियों को जन्म दिया है।

इन हालातों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस समस्या का समाधान ढूँढ़ने के लिए एक साथ बैठेंगे तो वे किसका हल तलाशेंगे, 'समस्या' का या किस 'किम जोंग' का?

इस प्रश्न के ईमानदार उत्तर में ही शायद समस्या और उसका समाधान दोनों छिपे हैं।

इसके लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम चर्चा में शामिल होने वाले राष्ट्र खुद को सुपर पावर की हैसियत

उत्तर कोरिया पर जापान का कब्जा था। इस युद्ध में जापान की हार के बाद कोरिया का विभाजन स्वरूप ट्रॉप्स और किम जोंग उन की जुबानी जंग लगातार आक्रमक होती जा रही है।

स्थिति तब और तनावपर्ण हो गई जब जुलाई में किम जोंग ने अपनी इन्टरकॉन्टेन्टल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।

क्योंकि न तो ट्रॉप्स ऐसे उत्तर कोरिया को स्वीकार करने के लिए तैयार है जिसकी इन्टरकॉन्टेन्टल बैलिस्टिक मिसाइलें न्यूयॉर्क की तरफ तनी खड़ी हों और न ही उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम बन्द करने के लिए।

इस समस्या से निपटने के लिए ट्रॉप्स का एशिया दौरा महत्वपूर्ण समझा



जा रहा है क्योंकि इस यात्रा में उनकी विभिन्न एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से उत्तर कोरिया पर चर्चा होने का भी अनुमान है।

मौजूदा परिस्थितियों में चूंकि देशों ही देश एटमी हथियारों से सम्पन्न हैं तो इस समय दुनिया एक बार फिर न्यूक्लियर हमले की आशंका का सामना करने के लिए अभिशप्त है।

निश्चित ही विश्व लगभग सात दशक पूर्व द्वितीय विश्वयुद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए न्यूक्लियर हमले और उसके परिणामों की भूल नहीं पाया है और इसलिए इस से मिलने वाली आर्थिक सहायता बन्द हो गई वहीं दूसरी तरफ इस देश ने उसी दौर में भयकर सूखे का भी सामना किया जिसमें उसके लाखों नागरिकों की मौत हुई और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

रही चीन की बात तो उसने उत्तर कोरिया के सामरिक महत्व को समझते हुए इसे केवल अमेरिका को साधने का साधन मात्र बनाए रखा। उत्तर कोरिया के साथ अपने व्यापार को चीन ने केवल अपने स्वार्थों तक ही सीमित रखा, उसे इतना भी नहीं बढ़ाने दिया कि उत्तर कोरिया खुद एक सामर्थ्यवान अर्थव्यवस्था बन जाए।

नीतीजन आज उत्तर कोरिया के सम्पूर्ण विश्व में केवल चीन के ही साथ सीमित व्यापारिक संबंध हैं।

इन हालातों में दुनिया को किम जोंग तरकीन और सनकी लग सकते हैं लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो उनका मौजूदा व्यवहार केवल अपनी सत्ता और सत्तानात को बचाने के लिए है क्योंकि किम ने सद्दाम हुसैन और मुअम्मर अल - गद्दाफी का हश्र देखा है।

इसलिए इन हथियारों से किम

शायद के बावजूद कोरिया पर जापान का कब्जा था। इस युद्ध में जापान की हार के बाद कोरिया का विभाजन स्वरूप ट्रॉप्स और किम जोंग उन की जुबानी जंग लगातार आक्रमक होती जा रही है।

स्थिति तब और तनावपर्ण हो गई जब जुलाई में किम जोंग ने अपनी इन्टरकॉन्टेन्टल ब

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् के बढ़ते कदम

देश के निर्यात क्षेत्र में हस्तशिल्प उत्पादों की अहम भूमिका है। वर्ष दर वर्ष देश के हस्तशिल्प उत्पादों में पश्चिमी और अन्य देशों की रूचि में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2016 – 17 के दौरान भारत से कुल 24,392.39 करोड़ रूपये के हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात किया गया। गत वर्ष के मुकाबले हस्तशिल्प निर्यात में 13.15 प्रतिशत की वृद्धि दर की गई। देश भर में करीब 6 करोड़ लोग हस्तशिल्प और उससे संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत हैं। हस्तशिल्प क्षेत्र का महत्व इस बात से भी प्रतीत होता है कि बड़े उद्योगों की तुलना में हस्तशिल्प क्षेत्र में बहुत कम निवेश के साथ बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान करने की अहम क्षमता है।

हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र देश के सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्रों में शामिल हैं। वस्त्र मंत्रालय की वित्त वर्ष 2016 – 17 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र ने क्रमशः 43.31 लाख और 68.86 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। इन दोनों क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्यात से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आय भी प्राप्त होती है। इसके साथ ही हथकरघा और हस्तशिल्प भारत की विरासत का मूल्यवान और अभिन्न अंग है, जिसे सरांक्षित रखने और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

- राकेश कुमार -

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् (ईपीसीएच) देश में हस्तशिल्प निर्यात और दुनियाभर में हस्तशिल्प उत्पादों की ब्राइंग बनाने के लिए नॉडल संस्था है। देशभर से हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े 11 हजार से अधिक संस्थाएं और

योजनाओं की सराहना की। यह योजना ओपन स्कूलों के जरिये कारीगरों के बच्चों को शिक्षा में पूरी सहायता प्रदान करती है। इसमें 75 प्रतिशत खर्च ईपीसीएच द्वारा तथा 25 प्रतिशत निर्यातक सदस्य द्वारा उठाया जाएगा।

है और हस्तशिल्प क्षेत्र के भागीदारों के बीच वैशिक हस्तशिल्प निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। विश्व भर में भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों की मांग में निरंतर वृद्धि होने के बाद भी हस्तशिल्प निर्यात बाजार में भारत की केवल पांच प्रतिशत भागीदारी है।

मेले के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और जोधपुर के हस्तशिल्प कलस्टर पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। इनमें जोधपुर के कारीगरों ने चमड़े की कढाई, सींग, टाई एवं डाई शिल्प, कढाई एवं ऐप्लीक, हाथ लॉक छपाई, पंजा दरी, धातु कला उत्पाद और काष्ठ शिल्प से जुड़ी अपनी शिल्प कला का प्रदर्शन कर सबका मन मोह लिया।

मेले के दौरान अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी से लघु और भविष्य के उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे अन्य व्यक्तियों को उत्पाद डिजाइन और नए उत्पादों के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा करेगा ताकि वे भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों से जुड़ सकें।

प्रौद्योगिकी उन्नयन के बारे में अगले पांच वर्ष के लिए ईपीसीएच ने

राज्यों, अनुसूचित जाति और जनजाति और महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। इसी नीति के अनुरूप लघु, छोटे और मध्यम क्षेत्र के उद्यमी निर्यातकों की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

के खरीदारों ने मेले का दौरा किया जबकि गत वर्ष 88 देशों से खरीदार मेले में पहुंचे थे। इसके साथ ही इस वर्ष मेले में प्रदर्शकों की संख्या बढ़कर लगभग तीन हजार तक पहुंच गई। मेले में 14 उत्पाद श्रेणियों में विभिन्न



व्यक्ति हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् के सदस्य है।

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् वार्षिक दो प्रमुख मेलों का आयोजन करती है जिनसे हस्तशिल्प निर्यात को प्रोत्साहन मिलने के साथ – साथ हस्तशिल्प उत्पादों को संपूर्ण विश्व के समक्ष बेहतर प्रस्तुति का अवसर प्राप्त होता है।

ग्रेटर नोएडा में 44वें भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले का आयोजन इसकी एक कड़ी था। इसका उद्घाटन केंद्रीय वस्त्र एवं सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में वस्त्र मंत्री ईरानी ने हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् की भूमिका की सराहना की। उहोने कहा कि हस्तशिल्प के निर्यात में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई है और यह 2016 – 17 में 13.15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 24,392 करोड़ रूपये पर पहुंच गया। उहोने ईपीसीएच द्वारा कारीगरों के बच्चों की शिक्षा के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पिरिराज सिंह ने हस्तशिल्प क्षेत्र के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हस्तशिल्प क्षेत्र देश में रोजगार प्रदान करने वाले सबसे बड़े क्षेत्र में से एक



विजन डाक्यूमेंट तैयार किया है। ईपीसीएच ने हाल ही में डिजाइन और उत्पाद विकास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है। ईपीसीएच ने हमेशा से पूर्वोत्तर

हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन किया गया था। इनमें प्रमुख रूप से घर, जीवन शैली, फैशन, हस्तशिल्प और फर्नीचर में दो हजार से अधिक उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इस वर्ष विदेशों से खरीदारों और उनके प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़कर 5995 तक पहुंच गई जबकि गत वर्ष यह 5586 थी। घरेलू व्यापारिक दौरा करने वालों की संख्या इस वर्ष 765 रही। मेले के दौरान 3150 करोड़ रूपये की व्यापारिक पूछताछ की गई और इसमें गत वर्ष के मुकाबले 6.78 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

इस वर्ष अमेरिका से सबसे अधिक 751 खरीदार, जर्मनी से 259, ब्रिटेन से 295, ऑस्ट्रेलिया से 275, फांस से 282, जापान से 194 और चीन से 67 खरीदार मेले में पहुंचे थे। इस वर्ष पहली बार जॉर्डन, कतर, लेबनान, सऊदी अरब, तुर्की, उजबेकिस्तान, हंगरी, मंगोलिया, लीबिया और केन्या से खरीदार मेले में पहुंचे। मेले के दौरान पुनः उपयोग किए उत्पादों का सजावट के लिए प्रयोग सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। पसूका

लाल दलीचा बिछु देश के पहले मतदाता सौ साल के श्याम सरन की खातिर

शिमला / शैल। आजाद भारत पहले मतदाता सौ साल के श्याम सरन नेगी ने एक बार फिर अपना मत डाल कर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत की तस्वीर की है। उनके जज्बे व लोकतंत्र में उनके

लिए खास इंतजाम किए थे। मतदान केंद्र पर पहुंचने पर जिला चुनाव अधिकारी व जिला उपायुक्त डॉक्टर नरेश कुमार लट्ठ और उनकी पत्नी तृप्ता लट्ठ ने श्याम सरन नेगी की अगुवाई की। इस मौके पर उन्हें खास



भरोसे को सलाम करते हुए चुनाव आयोग ने उनके लिए लाल दलीचा बिछाया। ये पहली बार है कि देश के किसी मतदाता के लाल दलीचा व उनकी पत्नी उन्हें मतदान केंद्र के भीतर ले गए। चुनाव आयोग ने उनके

तौर किन्नौर की परंपरागत टोपी 'तमका' पहनाई गई। इसके अलावा शॉल भी पहनाई गई। जिला उपायुक्त व उनकी पत्नी उन्हें मतदान केंद्र के भीतर ले गए।

जहां पर श्याम सरन नेगी ने अपने मतदान का इस्तेमाल किया। श्याम सरन नेगी ने 29वीं बार अपने मत का प्रयोग किया। श्याम सरन नेगी ने आजादी के बाद पहली बार 1951 में हुए आम चुनावों में पहली बार मतदान किया था। तब से लेकर अब तक वो लगातार मतदान करते रहे हैं। 2010 में देश के तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला चुनाव आयोग की हीरक जयंती पर खास तौर पर उनके घर कल्पा गए थे और उन्हें सम्मानित किया था।

जिला संपर्क अधिकारी ममता नेगी ने बताया कि सुबह 11 बजे के करीब चुनाव आयोग का विशेष वाहन कल्पा में उनके घर पहुंचा व जिला युवा खेल अधिकारी लाल सिंह नेगी उन्हें कल्पा के मतदान केंद्र 2 में ले गए। यहां पर उन्हें लाल दलीचा बिछाया गया और किन्नौरी टोपी व शॉल पहना कर उन्हें सम्मानित किया गया। मतदान के बाद उन्हें विशेष वाहन से घर छोड़ा गया।

वीरभद्र, विक्रमादित्य और धूमल ने डाला वोट पर किसी और को नहीं

शिमला / शैल। मौजूदा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर में और भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद के



हलका बदल दिया था। उन्हें हमीरपुर के बजाय सुजानपुर से लड़ाया गया। जबकि धूमल का वोट हमीरपुर हलके के समीरपुर में है। धूमल को



उनके बेटों भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, छोटे पुत्र अरुण धूमल व बाकी सदस्यों के वोट भी नहीं मिले। इन सबके वोट सुजानपुर के बजाय समीरपुर में हैं। इस बार के चुनाव में ये दिलचस्प हैं। हालांकि वीरभद्र सिंह व उनके परिवार को वोट हमेशा ही किसी को ओर गया है। पहले वो रोहडू से चुनाव लड़ते थे। जबकि उनका महल रामपुर में है। रोहडू के बाद उन्होंने अपना लिए शिमला ग्रामीण सीट चुनी और इस बार वो अर्की से चुनाव मैदान में है।

कांग्रेस से भाजपा में गए दूरसंचार घोटाले के दोषी सुखराम व मंडी से भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा ने मंडी में वोट डाला। इनके अलावा वीरभद्र सरकार के सभी मंत्रियों ने सुबह ही वोट डाल दिया जबकि भाजपा के बड़े नेता सुबह 11 बजे से पहले मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके थे।

माकपा प्रत्याशी राकेश सिंह ने कोटगढ़ में पूर्व कोट्री मंत्री आनंद शर्मा ने शिमला के केल्टी में वोट डाला। कई जगहों पर इवीएम में चुनाव लड़ रहे हैं।

इसी तरह भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का भी

अपने पति और न अपने पुत्र के लिए वोट डाल पाई। इन तीनों के वोट रामपुर में हैं। जबकि वीरभद्र सिंह अर्की हलके से चुनाव मैदान में है और विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं।

इसी तरह भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का भी

अपने पति और न अपने पुत्र के लिए वोट डाल पाई। इन तीनों के वोट रामपुर में हैं। जबकि वीरभद्र सिंह अर्की हलके से चुनाव मैदान में है और विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं।

इसी तरह भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का भी

अपने पति और न अपने पुत्र के लिए वोट डाल पाई। इन तीनों के वोट रामपुर में हैं। जबकि वीरभद्र सिंह अर्की हलके से चुनाव मैदान में है और विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं।

इसी तरह भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का भी

अपने पति और न अपने पुत्र के लिए वोट डाल पाई। इन तीनों के वोट रामपुर में हैं। जबकि वीरभद्र सिंह अर्की हलके से चुनाव मैदान में है और विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं।

इसी तरह भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का भी

अपने पति और न अपने पुत्र के लिए वोट डाल पाई। इन तीनों के वोट रामपुर में हैं। जबकि वीरभद्र सिंह अर्की हलके से चुनाव मैदान में है और विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं।

इसी तरह भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का भी

अपने पति और न अपने पुत्र के लिए वोट डाल पाई। इन तीनों के वोट रामपुर में हैं। जबकि वीरभद्र सिंह अर्की हलके से चुनाव मैदान में है और विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं।

इसी तरह भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का भी

अपने पति और न अपने पुत्र के लिए वोट डाल पाई। इन तीनों के वोट रामपुर में हैं। जबकि वीरभद्र सिंह अर्की हलके से चुनाव मैदान में है और विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं।

इसी तरह भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का भी

अपने पति और न अपने पुत्र के लिए वोट डाल पाई। इन तीनों के वोट रामपुर में हैं। जबकि वीरभद्र सिंह अर्की हलके से चुनाव मैदान में है और विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं।

इसी तरह भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का भी

अपने पति और न अपने पुत्र के लिए वोट डाल पाई। इन तीनों के वोट रामपुर में हैं। जबकि वीरभद्र सिंह अर्की हलके से चुनाव मैदान में है और विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं।

लगनी चाहिए। इस तरह की सिफारिशें इलेक्ट्रॉनिक रिफार्म कमेटी की रिपोर्ट में की गई हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की स्वायत्ता बहाल करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त व बाकी दो आयुक्तों की नियुक्ति व उन्हें हटाने की प्रक्रिया देश के मुख्य न्यायाधीश की तरह होनी चाहिए।

चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब, पैसा जैसे हथकंडों को अपनाने वाले प्रत्याशियों के विलाफ जांच व कार्रवाई करने व उन्हें अयोग्य ठहराने की शक्तियां चुनाव आयोग के पास होनी चाहिए। नोटा को ज्यादा प्रभावी बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा दोषी व अपराधी विलिंग के विलाफ उनकी संस्था हाईकोर्ट गई थी।

उन्होंने कहा कि वो इन तमाम बिंदुओं पर वो सुप्रीमकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेगे या पहले से चुनाव सुधारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं में वो पार्टी बनने के लिए अर्जी देंगे।

राजेश्वर नेगी हिमाचल में पर्यावरण व वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर सक्रिय रहे हैं व बंदरों की कलिंग के विलाफ उनकी संस्था हाईकोर्ट गई थी।

इसी तरह भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का भी

अपने पति और न अपने पुत्र के लिए वोट डाल पाई। इन तीनों के वोट रामपुर में हैं। जबकि वीरभद्र सिंह अर्की हलके से चुनाव मैदान में है और विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं।

इसी तरह भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का भी

अपने पति और न अपने पुत्र के लिए वोट डाल पाई। इन तीनों के वोट रामपुर में हैं। जबकि वीरभद्र सिंह अर्की हलके से चुनाव मैदान में है और विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं।

इसी तरह भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का भी

अपने पति और न अपने पुत्र के लिए वोट डाल पाई। इन तीनों के वोट रामपुर में हैं। जबकि वीरभद्र सिंह अर्की हलके से चुनाव मैदान में है और विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं।

इसी तरह भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का भी

अपने पति और न अपने पुत्र के लिए वोट डाल पाई। इन तीनों के वोट रामपुर में हैं। जबकि वीरभद्र सिंह अर्की हलके से चुनाव मैदान में है और विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं।

इस

आधार की अनिवार्यता के

स्थिलाफ अब भाजपा के नेता भी आवाज उठाने लगे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रह्मण्यम् स्वामी ने आधार पर तीरी टिप्पणी करते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। स्वामी ने यह भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आधार की अनिवार्यता के मामले को खारिज कर देगी। उन्होंने आधार संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई), को समाप्त करने की वकालत करते हुए इसे विधवांसंक बताया। उनके अनुसार, आधार डाटा फाइंग का काम विदेशी कंपनियां करती हैं, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा है। इस बाबत वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिख गए। दूसरी ओर आधार को लेकर केंद्र सरकार की समस्याएं और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इसके स्थिलाफ दायर दो दर्जन से अधिक याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट इस महीने के अंतिम सप्ताह में सुनवाई आरंभ करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल सिम को आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ने के स्थिलाफ दायर एक अन्य याचिका को सुनवाई हेतु स्वीकार कर ली है, जबकि बंगाल सरकार की याचिका को ठुकरा दिया है। कोर्ट का मानना है कि कोई भी राज्य सरकार केंद्र के कदम को चुनौती नहीं दे सकती। इसलिए परिषिक बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका खारिज कर दी गई। सुश्री बनर्जी ने पहले ही आधार को मोबाइल नंबर से लिंक कराने को लेकर अपना विरोध जता चुकी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इन सब मामलों की जल्द सुनवाई करेगी। उल्लेखनीय है कि नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि निजता का अधिकार संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार है। आधार की वैधानिकता को चुनौती देने वाली अनेक याचिकाओं में दावा किया था कि इससे निजता के अधिकार का हनन होता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि केन्द्र इस मामले में बहस के लिए तैयार है और अब इस मामले में उनका पक्ष सुने बगैर किसी अन्य अंतर्रिम आदेश की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ही न्यायालय ने कहा कि संविधान पीठ नवंबर के अंतिम सप्ताह में इस पर सुनवाई शुरू करेगी। केन्द्र की पहल का विरोध करते हुए याचिकायें दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम ने कहा कि शीर्ष अदालत ने पहले आधार मामले में कई आदेश पारित किये थे और कहा था कि यह विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक कृत्य है और कोई भी नागरिक सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए यह कार्ड रखने को बाध्य नहीं होगा। इस आदेश का पालन नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि 30 मार्च 2017 को दक्षिण पश्चिमाई विदेशी सरकार द्वारा नियमित विशिष्ट पहचान संरचना (आधार) को संविधान और कानून की अनदेखी करार दिया। इसमें इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि राजनीतिक विरोध के बावजूद इस मामले में खामोशी आश्चर्यजनक है।

अभी पिछले दिनों झारखंड के सिमेडोगा जिले में संतोषी नामक लड़की की मौत आधार के अभाव से हो गई। फिर केन्द्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने “आधारहीन” लोगों को भी राशन देने का ऐलान किया,

“आधार” पर वार क्यों?

Dr RP Srivastava

रामले पर अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है।

वास्तव में आधार का बायोमेट्रिक होना आपत्ति का बड़ा विषय बना हुआ है। अब सरकार भी कहीं न कहीं यह महसूस कर रही है कि इसकी अनिवार्यता/बाध्यता जनता के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। यह वही कार्ड है, जो दुनिया के कई देशों में विफल हो चुका है। यह जी एस टी की भाँति सरकार गिरानेवाला नहीं है, किन्तु हमारे देश में कांग्रेस सरकार के पतन में इसका बड़ा हाथ रहा है। उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी 2009 को कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने गैर कानूनी ढंग से बिना संसद द्वारा पारित कदम को जबरन नागरिकों पर थोथा था और रसोई गैस सिलिंडर के लिए आधार कार्ड की अमलन बाध्यता करके पूरे देश में नोटबंदी जैसी लाइनें लगवा दीं। सिर्फ विवाह के तौर पर कहा जाता रहा कि यह ऐच्छिक है। लेकिन व्यावहारिक रूप में इसे अनिवार्य बना दिया गया। सभी ने देखा, चुनाव में कांग्रेस का खेमा उखड़ गया। भाजपा के ही प्रस्ताव पर कांग्रेस ने यह कदम उठाया था, जो कांग्रेस के लिए भास्मायी साबित हुआ। कहते हैं कि भाजपा के किसी सज्जन ने एक अंग्रेजी उपन्यास में ऐसे कार्ड की कल्पना की कल्पना के बारे में पढ़ा था, जो अनोखा और चमत्कारिक था। फिर इसे ही भाजपा ने प्रस्तावित कर दिया, जबकि कांग्रेस एक दूसरा पहचान पत्र लाना चाहती थी, जिसके बनाने का एक चरण परा हो गया था और कांग्रेस के बहुदेशीय कार्ड पर करोड़ों रुपए फूँके जा चुके थे। हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में एक समय ऐसा भी आया था, जब भाजपा आधार का विरोध करने लगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आधार कार्ड के घोर विरोधी थे। ऐसा समय आया था, जब नरेंद्र मोदी रुद्रगंग और चमत्कारिक इतिहास के तब उन्होंने आधार कार्ड के लिये तत्कालीन यूपीए सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि अगर वे लोग इसी तरह से अंधाधूंध आधार बांटते रहेंगे तो हमारे गुजरात में आतंकियों के घुसने का खतरा बढ़ जाएगा। मोदी ने तब कहा था कि आज कांग्रेस वाले जिस आधार कार्ड को लेकर इतना नाच रहे हैं, उसे देख कर लगता है कि देश के लोगों को पता नहीं कौन सी जड़ीबूटी बाट रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा था कि ये आधार कार्ड से लाभ किसको मिलेगा? आधार कार्ड से क्या बाहरी लोग हमारे देश के नागरिक नहीं बन जाएंगे? परन्तु केन्द्रीय सत्ता पाते वे आधार के सबसे बड़े पैरोकार हो गए, यहाँ तक कि जब लोकसभा में विपक्षी दलों ने कहा कि जब यह सामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो कानून बनाने कि जल्दी क्या है? तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कह दिया कि उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। बाद में एक वित्त विधेयक को कानूनी जामा पहनाकर इस कम को आगे बढ़ाया गया, लेकिन इस कानून के विलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। इस पूरे

इस बाबत गोपनीयता के अधिकार के रक्षार्थ सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी मौजूद हैं। निजता के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ नागरिकों के मौलिक अधिकारों में सामिल कर चुकी है। शायद इसी तथ्य को देखते हुए डा.स्वामी कहते हैं कि “मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड को रद्द कर देगी” यह भी गैरतलब है कि मोदी सरकार ने आधार को कानूनी जामा पहनाने के लिए वित्त विधेयक लाभ अंतरण योजना से आधारकार्ड को जोड़ दिया है। आधार को एक तिहाई उपभोक्ता बैंकिंग और सामाजिक सेवा की पहुंच से बाहर है। ये लोग गरीब हैं, इसलिए खुद बाजार तक नहीं पहुंच सकते। पहचान (आधार, नंबर भिलते ही मोबाइल फोन के जरिए इन तक पहुंचा जाना जाना जाता है) ने जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), अध्यक्ष थे उन्होंने एक अवसर पर कहा था कि “भारत के एक तिहाई उपभोक्ता बैंकिंग और सामाजिक सेवा की पहुंच से बाहर हैं। ये लोग गरीब हैं, इसलिए खुद बाजार तक नहीं पहुंच सकते। पहचान (आधार, नंबर भिलते ही मोबाइल फोन के जरिए इन तक पहुंचा जाना जाना जाता है) ने जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), अध्यक्ष थे उन्होंने एक अवसर पर कहा था कि “भारत के एक तिहाई उपभोक्ता बैंकिंग और सामाजिक सेवा की पहुंच से बाहर है। ये लोग गरीब हैं, इसलिए खुद बाजार तक नहीं पहुंच सकते। पहचान (आधार, नंबर भिलते ही मोबाइल फोन के जरिए इन तक पहुंचा जाना जाना जाता है) ने जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), अध्यक्ष थे उन्होंने एक अवसर पर कहा था कि “भारत के एक तिहाई उपभोक्ता बैंकिंग और सामाजिक सेवा की पहुंच से बाहर है। ये लोग गरीब हैं, इसलिए खुद बाजार तक नहीं पहुंच सकते। पहचान (आधार, नंबर भिलते ही मोबाइल फोन के जरिए इन तक पहुंचा जाना जाना जाता है) ने जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), अध्यक्ष थे उन्होंने एक अवसर पर कहा था कि “भारत के एक तिहाई उपभोक्ता बैंकिंग और सामाजिक सेवा की पहुंच से बाहर है। ये लोग गरीब हैं, इसलिए खुद बाजार तक नहीं पहुंच सकते। पहचान (आधार, नंबर भिलते ही मोबाइल फोन के जरिए इन तक पहुंचा जाना जाना जाता है) ने जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), अध्यक्ष थे उन्होंने एक अवसर पर कहा था कि “भारत के एक तिहाई उपभोक्ता बैंकिंग और सामाजिक सेवा की पहुंच से बाहर है। ये लोग गरीब हैं, इसलिए खुद बाजार तक नहीं पहुंच सकते। पहचान (आधार, नंबर भिलते ही मोबाइल फोन के जरिए इन तक पहुंचा जाना जाना जाता है) ने जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), अध्यक्ष थे उन्होंने एक अवसर पर कहा था कि “भारत के एक तिहाई उपभोक्ता बैंकिंग और सामाजिक सेवा की पहुंच से बाहर है। ये लोग गरीब हैं, इसलिए खुद बाजार तक नहीं पहुंच सकते। पहचान (आधार, नंबर भिलते ही मोबाइल फोन के जरिए इन तक पहुंचा जाना जाना जाता है) ने जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), अध्यक्ष थे उन्होंने एक अवसर पर कहा था कि “भारत के एक तिहाई उपभोक्ता बैंकिंग और सामाजिक सेवा की पहुंच से बाहर है। ये लोग गरीब हैं, इसलिए खुद बाजार तक नहीं पहुंच सकते। पहचान (आधार, नंबर भिलते ही मोबाइल फोन के जरिए इन तक पहुंचा जाना जाना जाता है) ने जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), अध्यक्ष थे उन्होंने एक अवसर पर कहा था कि “भारत के एक तिहाई उपभोक्ता बैंकिंग और सामाजिक सेवा की पहुंच से बाहर है। ये लोग गरीब हैं, इसलिए खुद बाजार तक नहीं पहुंच सकते। पहचान (आधार, नंबर भिलते ही मोबाइल फोन के जरिए इन तक पहुंचा जाना जाना जाता है) ने जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), अध्यक्ष थे उन्होंने एक अवसर पर कहा था कि “भारत के एक तिहाई उपभोक्ता बैंकिं

क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी दल सता में आकर कारबाई कर सकेगा

शिमला / शैल। कांग्रेस और भाजपा के घोषणापत्रों में यह दावा किया गया है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर कर्तई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। कांग्रेस ऐसी शिकायतों का निवारण करने के लिये एक आयुक्त नियुक्त करेगी। भाजपा इसके लिये आयोग का गठन करेगी। कांग्रेस-भाजपा के चुनाव घोषणा पत्रों पर आम आदमी ने कितना धिन्तन - मनन किया होगा इसका अन्दराजा लगाना कठिन है। क्योंकि दोनों दलों ने जितने वायदे अपने घोषणा पत्रों में कर रखे हैं उन्हे पूरा करने के लिये धन कहां से आयेगा इसका जिक्र किसी ने भी नहीं किया है। भाजपा ने पानी पर प्रति क्यूबिक मीटर दस पैसे का कर लगाकर 600 करोड़ का राजस्व जुटाने का दावा किया है। लेकिन इस दस पैसे के कर से महंगाई पर कब कितना असर पड़ेगा इसका कोई जिक्र नहीं है। विकास के महत्वपूर्ण कार्यों के लिये पी पी मोड़ पर विदेशी फण्ड का प्रबन्ध किया जायेगा यह भी वायदा किया गया है। लेकिन इसके और परिणाम

क्या होंगे इस पर कुछ नहीं कहा गया है। कांग्रेस कृषि, बागवानी, पशुपालन आदि सारी योजनाओं पर 90% संधियों देगी और छोटे और सीमान्त किसानों को एक लाख ऋण व्याज मुक्त देगी तथा प्रतिवर्ष 30000 छात्रों को लैपटॉप देगी यह वायदा किया गया है। लेकिन इन वायदों को पूरा कैसे किया जायेगा इसका कोई जिक्र नहीं है। दोनों दलों के घोषणा पत्रों में जो वायदे किये गये हैं उन्हे पूरा करने के लिये या तो कर्ज का सहारा लिया जायेगा या फिर जनता पर करों का भार बढ़ाया जायेगा। क्योंकि वायदे पूरे करने के लिये धन चाहिये जो सरकार के पास है नहीं और केन्द्र इतना दे नहीं सकता क्योंकि उसकी भी कुछ वैधानिक सीमायें रहेंगी।

घोषणा पत्रों का यह जिक्र इस समय इसलिये आवश्यक है कि कल जो भी सरकार आयेगी वह अपने घोषणा पत्र से बंधी होगी। आम आदमी को अपेक्षा रहेगी कि सरकार के आते ही इन पर अमल शुरू हो जायेगा। इस अमल की आम आदनी को कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी इसके लिये उसे

पहले ही दिन से सजग रहना पड़ेगा। इस सजगता में आम आदमी यदि सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर किये गये वायदों पर ही सरकार को समय-समय पर सचेत करता रहेगा तो यही एक बड़ा काम होगा। दोनों दलों ने भ्रष्टाचार कर्तई बर्दाश्त न करने का वायदा किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कारबाई करने के लिये सरकार के पास विजिलैन्स का पूरा तन्त्र उपलब्ध है। लेकिन वीरभद्र के इस शासन काल में विजिलैन्स ने भ्रष्टाचार के किसी बड़े मामले पर हाथ डाला हो और उसमें सफलता हासिल की हो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि विजिलैन्स के पास कोई बड़ा मामला आया ही न हो बल्कि वास्तव में बड़े मामलों पर कारबाई करने से यह ऐजेन्सी बचती रही है। हिमाचल को विद्युत राज्य के रूप में प्रचारित प्रसारित किया जाता रहा है बल्कि इसी प्रचार के कारण यहां पर उद्योग आये हैं। लेकिन आज प्रदेश की विद्युत उसका आज तक कोई पता नहीं है। जे.पी. को 1990 में जो बसपा परियोजना दी गयी थी उसका 92 करोड़ वसूलने की बजाये बट्टे खाते में डाल दिया गया है। सीएजी इस पर एतराज उठा चुका है। लेकिन सरकार में कोई कारबाई नहीं हुई है। जे.पी. ने दूसरी के स्थान पर लगातार नुकसान से

अपने ही स्तर पर 1200 मैगावाट कर लिया और इस 300 मैगावाट का कोई अपप्रन्त प्रिमियम आज तक नहीं वसूला गया है। इसी तरह जो विद्युत परियोजनाएं विद्युत बोर्ड की अपनी हैं उनमें एक लम्बे अरसे से रिपेयर के नाम पर हर वर्ष हजारों घन्टों का शट डाऊन दिखाया जा रहा है।

इस परिदृश्य में यह स्मरणीय है कि प्रदेश में विद्युत में जे.पी. उद्योग समूह एक बड़ा विद्युत उत्पादक है लेकिन जितना बड़ा यह उत्पादक है राजस्व को लेकर इसके खिलाफ कारबाई करने के लिये सरकार के पास विजिलैन्स का पूरा तन्त्र उपलब्ध है। लेकिन वीरभद्र के इस शासन काल में विजिलैन्स ने भ्रष्टाचार के किसी बड़े मामले पर हाथ डाला हो और उसमें सफलता हासिल की हो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि विजिलैन्स के पास कोई बड़ा मामला आया ही न हो बल्कि वास्तव में बड़े मामलों पर कारबाई करने से यह ऐजेन्सी बचती रही है। हिमाचल को विद्युत राज्य के रूप में प्रचारित प्रसारित किया जाता रहा है बल्कि इसी प्रचार के कारण यहां पर उद्योग आये हैं। लेकिन आज प्रदेश की विद्युत उसका आज तक कोई पता नहीं है। जे.पी. को 1990 में जो बसपा परियोजना दी गयी थी उसका 92 करोड़ वसूलने की बजाये बट्टे खाते में डाल दिया गया है। सीएजी इस पर एतराज उठा चुका है। लेकिन सरकार में कोई कारबाई नहीं हुई है। जे.पी. ने दूसरी के स्थान पर लगातार नुकसान से

विद्रोह और भीतरघात के खिलाफ कारबाई के मायने सवालों में

शिमला / शैल। मतदान के बाद कांग्रेस और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जहां चुनाव परिणामों को लेकर अपने - अपने आंकलनों में जुटे हैं वहां पर दोनों पार्टीयों अपने - अपने विद्रोहियों और भीतरघातियों के खिलाफ कारबाई भी करने जा रही है। क्योंकि दोनों पार्टीयों को इन विद्रोहियों और भीतरघातियों से नुकसान पहुंचा है। दोनों पार्टीयों के आधा - आधा दर्जन विद्रोही अन्त तक बतौर आजाद उम्मीदवार चुनाव मैदान में बने रहे हैं। यह विद्रोही भले ही स्वयं न जीत पायें लेकिन अधिकृत उम्मीदवारों को अवश्य नुकसान पहुंचा सकते हैं यह माना जा रहा है। जहां एक ही चुनाव क्षेत्र में दोनों दलों के विद्रोही बतौर आजाद उम्मीदवार मैदान में बने रहे हैं वहां किसी आजाद को सफलता मिल सकती है इसकी संभावना भी बराबर है। यह विद्रोही कहां - कहां रहे हैं? इस सवाल की पड़ताल करने से पूर्व यह समझना बहुत आवश्यक है कि दोनों दलों में विद्रोही की स्थिति आयी ही क्यों।

सत्तारूढ़ कांग्रेस में मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह और संगठन प्रमुख सुकरु के बीच जिस तरह का टकराव सत्ता संभालने के पहले ही दिन से शुरू हुआ था वह चुनावों तक बराबर बना रहा है। लेकिन चुनावों में जब कुछ वीरभद्र के विश्वस्त माने जाने वाले निर्वलीयों के रूप में चुनाव मैदान में समाने आ गये तब मुख्यमन्त्री पर अपरोक्ष में अंगूलियां उठना शुरू हो गयीं। विद्रोहियों को आशीर्वाद देने और अधिकृत उम्मीदवारों को समर्थन न देने आक्षेप शिमला अर्बन और ठियोग विधानसभा क्षेत्रों में उस समय सामने आ गया जब एसआईडीसी के उपाध्यक्ष अनुल शर्मा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिये संगठन से निष्कासित किया गया। वीरभद्र ने इस निष्कासन का खुले रूप से विरोध करते हुए इसे अन्याय करार दिया है। इससे यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि कुछ पार्टी विद्रोहियों को वीरभद्र का समर्थन हालिस है। माना जा रहा है कि चुनावों के परिणाम आने के बाद एक बार फिर संगठन और वीरभद्र में खुले टकराव की नौबत आयेगी।

इसी तरह अगर भाजपा के भीतर उभरे विद्रोह का आंकलन किया जाये तो इसके लिये प्रदेश के स्थानीय नेताओं के हितों के अधोषित टकराव के साथ ही हाईकमान की नीति को भी बराबर का जिम्मेदार माना जा रहा है। केन्द्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद जब कई राज्यों में भी पार्टी की सरकारें बन गयी तो स्वभाविक रूप से कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ गया। इस मनोबल के बढ़ने के साथ ही उनकी अपनी महत्वकांक्षाएं भी बढ़ी और वह उम्मीद करने लगे की संगठन टिकटों के आवंटन में उन्हें भी तरजीह देगा। लेकिन जब टिकटों के लिये आवेदन किये जाने के पहले कार्यकर्ताओं और जनता में यह अप्रत्यक्ष प्रचार हो चुका था कि भाजपा में अगला मुख्यमन्त्री जेनी नड़ा होगे। धूमल के घोषित होने के साथ ही फिर पार्टी के भीतरी समीकरणों में बदलाव आया और इससे अपनी डफली अपने राग वाली स्थिति बन गयी।

इस परिदृश्य में यह स्पष्ट हो जाता है कि जब पार्टीयों का शीर्ष नेतृत्व अपने को ही सर्वेसर्वा मानकर अपने निर्णयों पर सार्वजनिक सहमति तैयार करने की बजाये उन्हें एक तानाशाह की तरह संगठन पर थोपने लग जाता है तब यह स्थितियां विद्रोह और भीतरघात की शक्ति लेकर सामने आती हैं फिर पार्टीयों जब ऐसे लोगों के खिलाफ निष्कासन के फैसले लेती हैं तो उन पर अन्त

तक अमल नहीं कर पाती है। 2012 के चुनावों में भी दोनों पार्टीयों ने ऐसे लोगों के खिलाफ निष्कासन की कारबाई को अंजाम दिया था। लेकिन इन चुनावों के आते - आते सबको फिर से शामिल कर लिया गया। भाजपा ने तो जांग्रेस से चुनावों में नेताओं को तोड़कर अपने टिकट थमाये हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि यदि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाता है और निर्वलीयों के सहयोग से सरकार बनाने की नौबत आती है तो क्या दल उन्हे अपने में शामिल करने से परहेज करेंगे। उस समय सरकार बनाने के लिये यह विद्रोह और भीतरघात सब बीते बक्त की बात हो जायेगी और इन आजाद लोगों को मंत्री बनाया जायेगा। नगर निगम शिमला में सत्ता के लिये अभी ही भाजपा यह सब कर चुकी है। इसलिये आज विद्रोह और भीतरघात के नाम पर कारबाई किये जाने का तब तक कोई अर्थ नहीं रह जाता है जब तक सत्ता का लालच बना रहेगा।